



2026:AHC:45929

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - **2611/2025**

श्रीमती जय कुमारीयाचिकाकर्ता

बनाम

बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जनपद बलिया एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शेष नाथ सिंह यादव, तेज बहादुर सिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. तत्काल रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग के लिए दायर की गई है:- "विद्वान बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी बलिया, जनपद बलिया के न्यायालय को यह निर्देश देने हेतु एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें कि वे उनके समक्ष लंबित अपील संख्या ?? 452 (जय कुमारी बनाम श्यामसुंदर और अन्य), जो यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 11 के तहत ग्राम बसंतपुर, परगना और तहसील बलिया, जिला बलिया के संबंध में दायर है, उसे इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित संक्षिप्त और निश्चित समय सीमा के भीतर, यदि संभव हो तो छह महीने की अवधि के भीतर तय करें।"
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले को शीघ्र तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। प्रतिवादी संख्या 1 को यह निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से उपरोक्त मामले को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से पांच महीने की अवधि के भीतर तय करें।
5. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

फरवरी 27, 2026

वी.आर.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"